दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/316 18 जुलाई 2026

Plexconcil/COA के सभी सदस्यों **को**

प्रिय सदस्य,

Plexconcil की ओर से नमस्ते!

भारत सरकार अभी इज़राइल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत कर रही है। इस बातचीत के हिस्से के तौर पर, सरकार ने 138 प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ़ ओरिजिन (PSR) पर इंडस्ट्री से इनपुट मांगे हैं, जिसमें सात मास्टरबैच शामिल हैं।

प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ से देखी जा सकती है: . https://docs.google.com/spread sheets/d/1Q5MQtcgP4air7yAumzHt TCpJZqn3P94t/edit?usp=sharing& ouid=108218688201736716589& rtpof=true&sd=true

भारत से इज़राइल को इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट लगभग USD 96 मिलियन और इम्पोर्ट USD 33 मिलियन का है।

एक मज़बूत और अच्छी तरह से तय प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल ऑफ़ ओरिजिन (PSR) ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि सिर्फ़ FTA पार्टनर देशों में सही मायने में बने प्रोडक्ट ही प्रेफरेंशियल टैरिफ बेनिफिट्स के लिए क्वालिफ़ाई करें। इससे तीसरे देशों से ट्रांसशिपमेंट या मिनिमल प्रोसेसिंग के ज़रिए आने वाले प्रोडक्ट्स द्वारा FTA कंसेशन का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी।

आपकी जानकारी के लिए, इज़राइल ने अपने मौजूदा FTA के तहत जो PSR अपनाए हैं, वे इस तरह हैं:

- इज़राइल-वियतनाम FTA: **CTH या नॉन-ओरिजिनेटिंग मटीरियल की 50% वैल्यू (VNOM)**
- इज़राइल-UAE FTA: **चैप्टर 39 के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए CTH या 40% क्वालिफाइंग वैल्यू कंटेंट (QVC)**
- इज़राइल-कोरिया FTA: **CTH या मैन्युफैक्चर जिसमें इस्तेमाल होने वाले नॉन-ओरिजिनेटिंग मटीरियल (NOM) की वैल्यू 60% से ज़्यादा न हो**
- इज़राइल-मर्कोसुर एफटीए: **सीटीएच या 50% वीएनओएम**

आप ऊपर दिए गए लिंक से ये डिटेल देख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया-इज़राइल FTA के लिए सही PSR पर सुझाव दें, साथ ही प्रपोज़्ड रूल के लिए एक छोटा सा जस्टिफिकेशन भी दें।

कृपया अपने इनपुट सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे तक bharti@plexconcil.org और research@plexconcil.org पर भेजें।

आपके कीमती इनपुट से भारत सरकार को इंडस्ट्री की सिफारिशें बनाने में मदद मिलेगी।

साभार,
राजा नारायणन
वरिष्ठ प्रबंधक
प्लेक्सकॉन्सिल